बिहार विधान परिषद्

190वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 2

मंगलवार, तिथि **6 अग्रहायण, 1940 (श.)**
27 नवम्बर, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 10

1.	स्वास्थ्य विभाग	-	-	06
2.	ऊर्जा विभाग	-	-	02
3.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	-	-	01
4.	गन्ना उद्योग विभाग	-	-	01
			कुल योग –	10

व्यवस्था सुनिश्चित

1. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना स्थित गर्दनीबाग अस्पताल, राजवंशीनगर अस्पताल एवं न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में नामित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इन तीनों अस्पतालों में संसाधनों, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों एवं कर्मियों के अभाव में अस्पताल में आये गंभीर मरीजों को उनके इलाज के लिए पी.एम.सी.एच. रेफर कर दिया जाता है, जिससे पी.एम.सी.एच. में मरीजों की लम्बी कतार लगी रहती है और उनका नम्बर तक नहीं लग पाता है, अन्तत: अधिकांश गरीब मरीजों को प्राईवेट अस्पतालों में भर्ती के लिए विवश होना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गंभीर मरीजों को इलाज की सुविधाएं मुहैया कराने हेतु खंड 'क' में वर्णित अस्पतालों की आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मॉडल हॉस्पीटल

2. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा में सदर अस्पताल है;

(ख) क्या यह सही है कि आरा सदर अस्पताल में काफी संख्या में प्रत्येक दिन रोगी दिखाने के लिए आते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि आरा सदर अस्पताल को मॉडल हॉस्पीटल के रूप में विकसित करने की योजना प्रक्रियाधीन है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक आरा सदर अस्पताल को मॉडल हॉस्पीटल के रूप में विकसित कराना चाहती है?

पर्याप्त जमीन

3. **श्री रामईश्वर महतो** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अन्तर्गत पंचायत-कोइरिया पिपरा के वार्ड नं.-2 में (C.H.C.) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अवस्थित है जिसके पास भवन बनाने हेतु पर्याप्त जमीन है;

(ख) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय से दूर होने के कारण आस-पास के सभी ग्रामीणों को इलाज हेतु सदर हॉस्पीटल तक मरीज को ले जाने में अपनी जान भी गंवानी पड़ती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने हेतु उक्त समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड करना चाहती है, जिसके पास भवन बनाने हेतु पर्याप्त जमीन भी है, यदि हां तो कबतक?

मीटर लगाने की योजना

4. **श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में बिजली की आपूर्ति खुले बाजार से खरीद कर की जा रही है, क्या बाजार पर ऊंची कीमत के बावजूद हमारी निर्भरता नहीं बढ़ गई है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार सरकार बाजार से बड़ी मात्रा में बिजली खरीद रही है, जिस दर से बिजली खरीदी जा रही है, क्या इससे सस्ती बिजली बाजार में उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि नई तकनीक को आवश्यक बताकर पिछले 2-3 वर्षों से चार तरह के बिजली मीटर, बिजली कम्पनियों ने खरीदे, अगर हां तो भी और ना तो भी सरकार बताये कि फिर से नये मीटर लगाने की योजना कैसे तैयार हो गई;

(घ) क्या यह सही है कि सरकार की तमाम तरह की कोशिशों के बाद भी बिजली कम्पनी का घाटा बढ़ता ही जा रहा है;

(ङ.) क्या यह सही है कि 2005 में सत्ता में आते ही बंद पड़े कांटी थर्मल पावर को रिमॉडलिंग कराने का संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया था और केन्द्र सरकार की बी.आर.जी.एस. योजना से इस हेतु 1055 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए और 2008 में ही चालू होना था, क्या यह सही है कि पैसे खर्च हो गये और हालत जस की तस है, अगर चारों यूनिटों का काम समय पर पुरा कर लिया जाता तो बिहार में 1750 करोड़ रुपये की बिजली पैदा होती, क्या यह सरकार की विफलता नहीं?

शुल्क प्रदर्शित

5. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में रोगियों एवं सामान्य लोगों को विभिन्न प्रकार की जांच के लिए (असहाय) मरीजों को निजी पैथोलॉजी केन्द्र में जाकर जांच करानी पड़ती है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के सभी पैथोलॉजी केन्द्र में जांच के लिए कोई मानक शुल्क, सूचना पट्ट पर अंकित नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि पैथोलॉजी केन्द्रों में जांच के लिए शुल्क प्रदर्शित नहीं रहने के कारण रोगियों से निर्धारित शुल्क से कहीं अधिक लिया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में पैथोलॉजी केन्द्रों पर सभी प्रकार की जांच के लिए सूचना पट्ट पर शुल्क प्रदर्शित कराना चाहती है?

मशीन की मरम्मती

6. **श्री रामचन्द्र पूर्वे** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि किडनी एवं हेपेटाइटिस बी के लगभग तीस मरीज प्रतिदिन डायलिसिस कराने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इस प्रतिष्ठित मेडिकल अस्पताल की 15 में से 12 डायलिसिस मशीनों के खराब होने के कारण मात्र दस (10) मरीजों का ही डायलिसिस हो पाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो मशीनों को ठीक नहीं कराने का क्या औचित्य है?

मीमारियों का इलाज

7. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली स्थित सरगंगा राम अस्पताल, चिकित्सा सुविधा के लिए एक विख्यात अस्पताल है, जहां बिहार के गरीब वर्गों के गंभीर मरीजों का तांता लगा रहता है, लेकिन यह अस्पताल प्राईवेट रहने के कारण यहां गंभीर रूप से पीड़ित गरीब मरीजों को इलाज कराने में भारी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि दिल्ली स्थित मेदांता मेडिसिटी अस्पताल सहित अन्य प्राईवेट अस्पतालों में इलाज कराने पर बिहार सरकार बिहारी मरीजों को इलाज की क्षतिपूर्त्ति प्रदान करती है, लेकिन यह प्रावधान सर गंगाराम अस्पताल के लिए नहीं किया जा सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सरगंगा राम अस्पताल में इलाज कराने वाले बिहारी मरीजों को भी इलाज को क्षतिपूर्त्ति देने का विचार रखती है, ताकि बिहारी गरीब मरीज भी सरगंगा राम अस्पताल में गंभीर बीमारियों का इलाज करा सके?

बोर्ड का गठन

8. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सन् 1973 में विधि विभाग के माध्यम से बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, धार्मिक न्यास बोर्ड, दिगम्बर जैन/श्वेतांबर बोर्ड, सिख धार्मिक न्यास सह गुरुमुखी बोर्ड के गठन हेतु प्रस्ताव शासन के समक्ष उपस्थापित किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित बोर्ड (सिख धार्मिक न्यास सह गुरुमुखी बोर्ड को छोड़कर) का गठन 7 अप्रैल 1973 को कर दिया गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अन्य बोर्डों की तरह बिहार में सिख धार्मिक न्यास सह गुरुमुखी बोर्ड का गठन कबतक करने जा रही है?

पोल हटाने पर विचार

9. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा शहर की बड़ी मस्जिद मेन रोड, रैन बसेरा मौलाबाग रोड, के.जी.रोड, वन स्टेप कोचिंग सेन्टर समीप क्लब रोड, नवादा चौक, मेन रोड, महादेव रोड, अनाइठ, स्टेशन रोड में बीच रोड पर बिजली का पोल है;

(ख) क्या यह सही है कि सड़क के बीच में बिजली का पोल रहने के कारण आने-जाने में वाहनों को काफी कठिनाई होती है, साथ ही पोल के कारण दुर्घटना भी होती है;

(ग) क्या यह सही है कि सड़क के बीच बिजली के पोल को हटाने के लिए कई बार विभाग के पास शिकायत करने के बाद भी बीच सड़क से पोल को हटाया नहीं जा सका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दुर्घटना को देखते हुए बीच सड़क से पोल कबतक हटाना चाहती है?

चीनी मिल चालू कबतक

10. **श्री प्रेमचन्द्र मिश्रा** : क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार राज्य की बंद पड़ी कतिपय चीनी मिलों को फिर से चलाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे प्रस्तावित चीनी मिलों की सूची में दरभंगा जिला की रय्याम चीनी मिल का नाम नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला अन्तर्गत आने वाली बंद पड़ी लोहट एवं सकरी चीनी मिल को फिर से चालू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बताना चाहेगी कि बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से कब चालू किया जायेगा?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 27 नवम्बर, 2018